पंजाब सरकार

हरपाल सिंह चीमा

वित्त मंत्री, पंजाब

द्वारा

पंजाब विधान सभा में

वर्ष 2023–24 का

बजट पेश करते समय दिया गया

भाषण

10 मार्च, 2023

चण्डीगढ़

बजट 2023-24

हरपाल सिंह चीमा

वित्त मंत्री

का भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. इस पावन सदन में आम आदमी पार्टी की सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आप सरकार के पहले बजट की तरह, इस बजट को भी डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार जब मैं अपना भाषण समाप्त कर लूंगा तो सभी बजट दस्तावेज एक मोबाइल ऐप/वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे।

2. पंजाब गुरुओं और संतों की भूमि है जिन्होंने समय-समय पर हमें एक स्वस्थ एवं खुशहाल समाज की अवधारणा के रूप में निर्देशित किया है। मैं श्री गुरु रविदास जी महाराज के एक शब्द को उद्धृत करना चाहता हूँ, जैसा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में निहित है जिसमें उन्होंने अपने आध्यात्मिक निवास के परिवेश की यह कहते हुए कल्पना की है:

ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ॥

ਦੂਖੁ ਅੰਦੋਹੁ ਨਹੀ ਤਿਹਿ ਠਾਉ॥

अर्थात "मेरा घर दुखों से मुक्त है, इसमें पीड़ा और चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है।"

3. माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु रविदास जी की बे-गम पुरा अवधारणा से प्रेरणा लेते हुए आप सरकार ने **"रंगले पंजाब"** बनाने की दिशा में निरंतर काम करने का संकल्प लिया है।

4. जब मैं अपनी सरकार द्वारा अपने पहले ही साल में की गई जनहितकारी पहलों को देखता हूँ तो मेरे दिल में संतोष की अनुभूति होती है। मैं यह भी जानता हूँ कि यह आराम करने का समय नहीं है। हमें 3 करोड़ पंजाबियों की लंबे समय से चली आ रही अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दोगुनी ताकत से काम करना है।

5. सरदार भगवंत सिंह मान जी स्वच्छ, प्रभावी और कुशल शासन प्रदान करने के लिए निरंतर (24x7) काम कर रहे हैं। सरदार भगवंत सिंह मान जी का भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का संकल्प पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। पंजाब को लूटने वालों में से कई पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। एक बार सर्वव्यापी और शक्तिशाली माफिया, आजकल कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हमने राजनीतिक इच्छाशक्ति और ईमानदार इरादों से भ्रष्टाचार और माफिया राज का कई क्षेत्रों से सफ़ाया किया है।

6. हमारी सरकार ने पिछले बजट के दौरान समाज के बुनियादी स्तंभों यानी शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए एक मिशन की घोषणा की थी। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आम आदमी क्लीनिक खुलने के बाद से ही 10.50 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला। इसके अलावा, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, मेरे पिछले भाषण में जिन "स्कूलज़ ऑफ एमिनेंस" का उल्लेख किया गया था, वे अब एक वास्तविकता बनने जा रहे हैं। हमारे लड़के और लड़कियां महंगे निजी स्कूलों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और वे इन "स्कूलज़ ऑफ एमिनेंस" के छात्र होने पर गर्व महसूस करेंगे।

अध्यक्ष महोदय,

7. पंजाबी युवाओं को नियमित नौकरी देना माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रतिबद्धता थी। इस वादे को पूरा करते हुए आप सरकार द्वारा सरकार और उसकी एजेंसियों में 26,797 नौकरियां पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। पिछली सरकारों के विपरीत, हम

प्रतिभा पलायन की प्रक्रिया को रोकने के लिए पंजाबियों के लिए नियमित रूप से भर्ती करेंगे और निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेंगे।

8. "जनता का धन केवल जनता के लिए" के आदर्श को ध्यान में रखते हुए, सरदार भगवंत मान सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के ऐतिहासिक निर्णय का पंजाब के हर वर्ग ने स्वागत किया है। पंजाब के लगभग 90% परिवारों को अब "जीरो बिजली बिल" मिल रहा है। इसी तरह आम पंजाबियों के लिए सार्वजनिक रेत खदानें खोलना एक और अभूतपूर्व फैसला है जो हमारी सरकार ने लिया है। यह आम लोगों को किफायती दामों पर अपने सपनों का घर बनाने में सक्षम बना रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ।

9. हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सक्षम मार्गदर्शन में स्थायी कृषि को पंजाब की सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का आधार मानते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा विविधीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देना, सरकार द्वारा मूंग की खरीद और मिल्कफेड उत्पादों के लिए भव्य विपणन योजना इस संबंध में अग्रणी कदम थे। इस वर्ष का बजट कृषि क्षेत्र को और गति प्रदान करेगा, जिसकी झलक मेरे भाषण के आगामी पैराग्राफों में नज़र आएगी।

10. हमारी सरकार ने पिछले साल राज्य के वित्त पर श्वेत पत्र जारी किया था, जिस के माध्यम से पिछली सरकारों के कारण हुए बुरे वित्तीय हालातों को गहराई से उजागर किया गया था। हमारी सरकार को हजारों करोड़ रुपए की लंबित देनदारियों विरासत में मिली हैं। मैं स्वर्गीय राहत इंदौरी साहिब का एक शेर पढ़ना चाहूंगा -

"हमसे पहले भी मुसाफ़िर कई गुज़रे होंगे

कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते"

11. आम आदमी पार्टी की सरकार हमारे पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ी गई बाधाओं को दूर करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने पंजाब कृषि विकास बैंक, पनसप, पंजाब एग्रो जैसे सहकारी संस्थानों को इस साल बड़ी वित्तीय राहत प्रदान की गई। इस के अलावा हमारी सरकार ने जिला सहकारी बैंकों में पूंजी डाली, मिल्कफेड को अनुदान प्रदान किया और हमारे मेहनती गन्ना उत्पादकों को समय पर भुगतान करने के लिए मिलों एवं शुगरफ़ेड को वित्तपोषित किया, और इस उद्देश्य के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपए दिए गए।

12. छठे वेतन आयोग के प्रभाव को, जिसे पिछली सरकार ने जानबूझ कर विलंबित किया था, हमारी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में उस का सामना साहसपूर्वक किया गया। हमारी सरकार ने अक्टूबर 2022 से 6% डीए जारी करके और यूजीसी वेतनमान और दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को लागू करके हमारे मेहनती अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। जब कि इस लाभ को पिछली सरकार द्वारा अदा किया जाना बनता था। इनके कारण राज्य के खजाने पर 1,150 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

13. इसके अलावा, लंबित देनदारियों को खत्म करने और जमीनी स्तर पर कार्यों को गति देने के लिए, हमारी सरकार ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित लगभग 1,750 करोड़ रुपए की असंवितरित राशि के पिछले वर्षों के केंद्रीय हिस्से को जारी किया, जिसे पिछली सरकारों ने रोक रखा था।

14. अपने पहले बजट भाषण के दौरान, मैंने अपनी सरकार की ओर से तीन मुख्य क्षेत्रों, यानी सुशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और राजस्व संग्रह पर काम करने का वादा किया था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने तीनों मानकों पर काम किया है। मैं हर पंजाबी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उसकी उम्मीदों को नीतियों और कार्यक्रमों में बदला जा रहा है, जो आने वाले समय में फलीभूत होंगे।

15. राजस्व को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा के फोकस क्षेत्रों का विस्तार करते हुए, इस वर्ष के लिए मुख्य केन्द्र बिन्दु इस प्रकार होंगे: -

क. कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देकर किसानों एवं श्रमिकों की आय बढ़ाने पर ध्यान देना;

ख. औद्योगिक प्रगती के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करना;

ग. विवेकपूर्ण पूंजीगत व्यय के माध्यम से अवसंरचनात्मक विकास को प्राथमिकता देना, ताकि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सके; और

घ. राज्य वित्त का मजबूतीकरण: संपत्ति मुद्रीकरण द्वारा वित्ती साधनों को बढ़ाना और तर्कशील ढंग से खर्च करना।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

16. केंद्र सरकार से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि केंद्र सरकार राज्य की 9,035 करोड़ रुपए की लंबे समय से लंबित वैध मांगों को अनसुना कर रही है। उदाहरण के लिए, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट में 31,000 करोड़ रुपए के क्लीन टर्म लोन से संबंधित 6,155 करोड़ रुपए के उचित दावों का सत्यापन किया था, जिसका भुगतान राज्य को नहीं किया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास शुल्क से खरीदे गए अनाज पर एमएसपी के 3% की दर से लगाया जा रहा है, जिसकी पहले एफसीआई द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही थी, से संबंधित 2,880 करोड़ रुपए को भी केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है।

17. भारत सरकार द्वारा पैदा की जा रही कठिनाइयों और हमारी पिछली सरकारों द्वारा छोड़े गए वित्तीय दलदल के बावजूद, हमारी सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से आम पंजाबियों को अच्छी तरह से योग्य वित्तीय राहत प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

वर्तमान आर्थिक स्थिति

18. अब, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष राज्य के प्रमुख मैक्रो-इकोनॉमिक संकेतकों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चालू वर्ष के लिए पंजाब का जीएसडीपी 6,38,023 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले वर्ष अर्थात 2021-22 की तुलना में 9.24% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की संभावित अनुमानित जीएसडीपी 6,98,635 करोड़ रुपए होगी। वर्ष 2022-23 में पंजाब के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक 45.91%, कृषि क्षेत्र का 28.94% एवं उद्योगों का 25.15% योगदान रहा। परंतु, 18.11% के अखिल भारतीय योगदान की तुलना में कृषि क्षेत्र अब भी राज्य जीएसडीपी में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर 7.40% की वृद्धि दर्ज करते हुए 1,73,873 रुपए रही।

सार्वजनिक वित्त को मजबूत करना

19. मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के वित्त के प्रबंधन में राजकोषीय विवेकपूर्णता और दक्षता लाने के लिए वादे के अनुसार अपेक्षित उपाय किए जा रहे हैं। प्रारंभ में, टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट को विधिवत अधिसूचित किया गया है जो वित्त वर्ष 2023-24 में पूरी तरह कार्यात्मक होगा, यह यूनिट करदाताओं द्वारा की गई कर चोरी और गैर-अनुपालन का पता लगाने और वसूली के लिए प्रणालीगत उपकरण विकसित करने में मदद करेगा। राज्य के राजस्व को और अधिक बढ़ाने के लिए कर और गैर-कर राजस्व धाराओं के संपूर्ण विस्तार की जांच के लिए विशेषज्ञों को काम पर रखा जा रहा है।

20. राज्य के वित्त को समेकित करने और राज्य के ऋण को उतारने के दोहरे उद्देश्य के साथ, मेरी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) में 3,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जबकि पिछले वर्षों के दौरान पिछली सरकारों

द्वारा पिछले 5 वर्षों में डाला गया योगदान केवल 2,988 करोड़ रुपए था।

21. इसके अलावा, प्रशासनिक विभागों कामकाज को सरल बनाने के लिए, व्यय प्राधिकरण जो पहले वित्त विभाग के अधिकार क्षेत्र में थे, को विधिवत रूप से संबन्धित विभागों को सौंप दिया गया है।

22. हम केंद्र सरकार के साथ यह मामला भी उठा रहे हैं कि पंजाब राज्य को उच्च लागत वाले पहले लिए गए ऋणों के स्थान पर कम ब्याज वाली दरों वाले ऋणों में तबदील किया जाए। जैसे कि राष्ट्रीय लघु बचत फ़ंड ऋण जिन की ब्याज दर 9.50% से 10.50% है, को बाजार में प्रचलित लगभग 7.60% की कम ब्याज दर के साथ स्वैप किया जाए। इससे राज्य को अपनी कठिन वित्तीय स्थिति से उबरने और राज्य की ब्याज देनदारियों को कम करने में मदद मिलेगी।

बजट 2023-24

माननीय अध्यक्ष महोदय,

23. मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,96,462 करोड़ रुपए के कुल बजट व्यय का प्रस्ताव रखता हूं जो वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) की तुलना में 26% की वृद्धि को दर्शाता है। प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः 3.32% और 4.98% आंका गया है।

24. मैं राज्य के राजस्व व्यय का अनुमान 1,23,441 करोड़ रुपए प्रस्तावित करता हूं जो वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमानों) के की तुलना में 14% की बढ़ोत्तरी दर्शाता है। इसमें से 74,620 करोड़ रुपए प्रतिबद्ध व्यय के लिए प्रस्तावित हैं, जो वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमानों) की तुलना में 12% की वृद्धि है।

25. प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट अनुमान 11,782 करोड़ रुपये है जो वित्त वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) से 22% अधिक है। सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विकास गतिविधियों के लिए लक्षित दृष्टिकोण अपनाएगी।

26. मैं अब राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2023-24 में की जाने वाली पहलों और कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित बजटीय आवंटन के साथ-साथ विकास रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहूंगा।

कृषि और किसान कल्याण

अध्यक्ष महोदय,

मैं डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के शब्द दोहराता हूँ, जिन्होंने कहा था "यदि कृषि असफ़ल हो जाती है, तो कुछ भी सफ़ल नहीं हो सकता।"

27. पंजाब के समाज और अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। हमारे राज्य के मेहनती किसानों ने अकेले भारत का भरण-पोषण किया, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र और राज्य सरकारों ने हमेशा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। मैं अपने किसानों द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों की सराहना करने के लिए अपना सिर झुकाता हूँ और नतमस्तक होता हूँ। मैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 13,888 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 20% अधिक है।

28. अपने बच्चों को पेट भरने में व्यस्त माँ की तरह, पंजाब को अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी। आज, हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य ने प्राकृतिक पोषक तत्वों को खो दिया है, जल स्तर काफी कम हो गया है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों ने हमारे पर्यावरण को जहरीला बना दिया है। इसलिए यह सुधार के लिए कदम उठाने का समय है। इस दिशा में

आगे बढ़ते हुए, हमारी सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से "नई कृषि नीति" लाने का प्रस्ताव रखा है। हम राज्य के लिए व्यापक कृषि नीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन पहले ही कर चुके हैं।

29. हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक परामर्शी और सहभागी पहल 'सरकार-किसान मिलनी' है, जिसे पंजाब के किसानों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। आने वाले महीनों में ऐसी और मिलनियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें किसानों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने और नीतिगत पहलों के लिए उनकी प्रतिक्रिया/सुझाव प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाएगा।

30. मैं यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष स्टेट नोडल एजंसी पनसीड द्वारा ट्रैक एवं ट्रेस सिस्टम द्वारा 38 करोड़ रुपए के 1 लाख क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीजों की खरीद की गई थी और लगभग 50,000 किसानों को 10 करोड़ रुपए के सब्सिडी वाले बीज उपलब्ध करवाए गए थे। इस पहल के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाए जाएं।

विविधीकरण (डायवर्सिफ़िकेशन)

31. यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कृषि में विविधीकरण को एक बड़ा प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। इसमें बासमती की खरीद के लिए सरकार शामिल होगी, जिसके लिए एक रिवाल्विंग निधि सृजित की जाएगी; कपास के बीजों पर 33% सब्सिडी दी जाएगी और हमारे किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता के लिए ट्रैक एंड ट्रेस म्कैनिज़्म स्थापित किया जाएगा। मैं वित्त वर्ष 2023-24 में विविधीकरण पर एक विशेष योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

32. हमारी सरकार ने प्रत्येक गांव में विस्तार सेवाएं प्रदान करने और किसानों के दरवाजे पर सूचना और जानकारी देने के लिए 2,574 "किसान मित्र" को शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल ग्राम स्तर पर रोजगार सृजित होगा बल्कि किसानों को कृषि में सर्वोत्तम तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी।

33. हमारी सरकार कृषि में स्थायी और पानी बचाने वाली प्रमुख पहलकदमियों के लिए आवश्यक बजटीय समर्थन जारी रखेगी। इस वर्ष दौरान 30,312 किसानों को 1,500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से "धान की सीधी बिजाई" करने पर 25 करोड़ रुपए वित्ती सहायता जारी की गई। आगामी धान के सीज़न में और अधिक किसानों द्वारा धान की सीधी बिजाई का विकल्प चुनने की उम्मीद है। हमारी सरकार ने पहली बार एमएसपी पर मूंग की फसल की खरीद की और 20,898 किसानों को लाभ देते हुए कुल 79 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफ़र की। मैं अगले वित्तीय वर्ष में इन दो पहलों के लिए 125 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

पराली को जलाने से रोकना

34. मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आप सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक लक्षित कार्यों के परिणामस्वरूप, धान की पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 30% तक की कमी आई है अर्थात खरीफ 2021-22 के दौरान 71,304 घटनाओं की तुलना में पंजाब में खरीफ 2022-23 के दौरान 49,922 घटनाएं सामने आईं। इसके अलावा, हमारी सरकार ने पंजाब में चल रहे लगभग 2,500 ईंट भट्ठों में ईंधन के रूप में 20% कोयले के स्थान पर धान की पराली के पैलेट्स के प्रयोग को अधिसूचित कर दिया है जो दिनांक 01.05.2023 से लागू हो जाएगा। इससे न केवल पराली प्रबंधन में मदद मिलेगी बल्कि सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे।

35. हमारी सरकार धान की पराली जलाने की इस प्रथा को खत्म करने के लिए विभिन्न संभावनाएं और समाधान प्रदान करके किसानों को अपने साथ जोड़ना जारी रखेगी। इसके अलावा, मैं उत्पादकता बढ़ाने और धान की पराली का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न मशीनों एवं उपकरणों को प्रदान करने के लिए कृषि तंत्र पर उप मिशन के तहत 350 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

किसानों को मुफ्त बिजली

36. हमारी सरकार ने हमारे अन्नदाताओं को वित्त वर्ष 2022-23 (सं. अनु.) में 9,064 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली प्रदान की है। आप सरकार इस सहायता को जारी रखेगी और वित्त वर्ष 2023-24 में इस उद्देश्य के लिए मैं 9,331 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

फसल बीमा

37. हम सभी जानते हैं कि खेती एक जोखिम भरा व्यवसाय है। हर साल, किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई फसल अप्रत्याशित मौसम या किसी बीमारी की चपेट में आ जाती है जिससे फसल खराब हो जाती है और किसानों का नुकसान हो जाता है। हमारी सरकार के नेक इरादे को प्रकट करते हुए मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि किसानों को मौसम की मार और अन्य अनिश्चितताओं से बचाने के लिए फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। फसल बीमा योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

बागवानी

38. बागवानी फसलें कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनके महत्व को समझते हुए, मैं अगले वित्तीय वर्ष के लिए 253 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ, जो वित्त वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) में आवंटित बजट के दोगुने से भी अधिक है।

39. मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप को सूचित करूं कि हमारी सरकार द्वारा बागवानी पर विशेष जोर देने के साथ पंजाब टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो एक्ट, 2020 को लागू करके टिश्यू कल्चर आलू की फसल के लिए सर्टीफ़िकेशन, ट्रेसबिलिटी और ब्लॉक-चेन तकनीक शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा, पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट, 1961 में राज्य नर्सरी को रोग मुक्त प्रमाणित बागवानी रोपण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए संशोधन किया गया है।

40. सरकार, फलों की फसलों के तहत उनके प्राकृतिक क्षेत्रों में क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, 5 नए बागवानी एस्टेट स्थापित करने का इरादा रखती है। ये एस्टेट लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, बठिंडा और फरीदकोट जिले में स्थित होंगे। मैं इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

41. हमारी सरकार ने बागवानी उत्पादकों के लिए एक नई जोखिम शमन योजना यानी 'भाव अंतर भुगतान योजना' शुरू करने का भी फैसला किया है। जब भी बाजार की कीमतों में निश्चित स्तर से अधिक की कमी आएगी तो सरकार कीमतों को स्थिर रखने के लिए प्रयास करेगी। मैं इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15 करोड़ रुपए रुपए के प्रारंभिक आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके अलावा फूलों के बीज उत्पादन के माध्यम से विविधीकरण के लिए एक नई योजना भी आगामी वित्तीय वर्ष में चालू की जाएगी।

42. मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर ने टिश्यू कल्चर के माध्यम से सेब की एक किस्म विकसित की है, जो पंजाब की जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 सालों में पंजाब के अपने सेब के बाग होंगे, जो फिलहाल सिर्फ पहाड़ी राज्यों में ही देखे जाते हैं।

सहकारिता

43. जैसा कि मैंने आरंभ में अपने भाषण में कहा था, हमारी सरकार ने कई संघर्षरत सहकारी संस्थाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। उदाहरण के लिए, पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक (पी.एस.सी.ए.डी.बी) को अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए 885 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं ताकि वे अपने नाबार्ड से लिए गए ऋण का निर्वहन कर सकें और पेंशनभोगियों के 2013 से लंबित देय लाभों का भुगतान कर सकें। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी) को उनके अच्छे काम को जारी रखने की सुविधा के लिए 135 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की गई है। इसी प्रकार मिल्कफेड को 36 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई।

44. गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरदार भगवंत सिंह मान जी ने राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली कीमत को बढ़ाकर 380 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। जबकि हरियाणा ने 372 रुपये प्रति क्विंटल, उत्तर प्रदेश ने 350 रुपये प्रति क्विंटल और भारत सरकार ने केवल 305 रुपये प्रति क्विंटल (एफ़.आर.पी) कीमत तय की है।

45. शूगरफेड को राज्य के गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने और सभी लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए 400 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। मैं शूगरफेड के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए के और आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहकारी चीनी मिलों के लिए चीनी कोटा बढ़ाने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष सफलतापूर्वक उठाया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके प्रयासों से चीनी मिलों को 50% का अतिरिक्त कोटा और निर्यात कोटा भी आवंटित किया गया है। इन सभी ने चीनी मिलों को सीरे और चीनी के तीन-चार साल से पड़े भंडारों को खत्म करने और पर्याप्त आमदन कमाने में मदद की।

46. इसके अलावा, गन्ने की कुशल प्रोसेसिंग और मूल्यवर्धन के लिए बटाला और गुरदासपुर में नए शुगर कंपलैक्सों की स्थापना के लिए, चालू वर्ष में 75 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। मैं इन परियोजनाओं में से लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपये और देने का प्रस्ताव रखता हूं।

47. हमारी सरकार डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे विश्व स्तरीय डेयरी उत्पादों का पूरा प्रचार हो। इस उद्देश्य के लिए मिल्कफेड एक तरफ गांवों में अपने खरीद नेटवर्क का विस्तार करेगा और दूसरी ओर अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बाजार में उतारेगा। मिल्कफेड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में मिल्कफेड के टर्नओवर को 4,886 करोड़ रुपए से दोगुना करके अर्थात वित्त वर्ष 2026-27 तक 10,000 करोड़ रुपए करने का इरादा रखती है।

48. मार्कफेड 13 स्थानों पर 1.75 लाख मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले नए गोदाम स्थापित कर रहा है, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 6 गोदामों का निर्माण मार्च, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। मैं अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में शेष 7 प्रोजैक्टों को पूरा करने के लिए फिर से 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूँ।

49. यह बड़ी खुशी की बात है कि मार्कफेड द्वारा खन्ना में कच्चे पाम तेल के प्रोसेसिंग के लिए एक नई 110 टन प्रति दिन (टी.पी.डी) फ़िज़िकल रिफाइनरी और 100 टन प्रति दिन (टी.पी.डी) वनस्पति प्लांट स्थापित किया जा रहा है और यह काम वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्कफेड द्वारा सरसों की फसल की प्रोसेसिंग के लिए बुढलाडा और गिद्दड़बाहा में दो नई तेल मिलें स्थापित की जाएंगी।

पशुपालन

50. इस वर्ष, पंजाब की पशुधन पर लंपी स्किन बीमारी का प्रकोप आया। इस बीमारी पर सफलतापूर्वक काबू पाने के लिए हमारी सरकार की ओर से कदम उठाते हुए पशुओं का समय से टीकाकरण करने हेतु गोट पॉक्स के टीके की लगभग 25 लाख खुराकें तुरंत खरीदी गईं। अब तक लगभग 7.45 लाख मवेशियों का टीकाकरण किया जा चुका है और भविष्य में इस बीमारी से निपटने के लिए पर्याप्त टीके उपलब्ध हैं। मुझे संतोष है कि भयंकर अफ्रीकी स्वाइन बुखार के गंभीर महामारी बनने से पहले ही हमारी सरकार ने उस पर तुरंत काबू पा लिया। उन सूअर पालकों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया गया, जिनके सूअर अफ्रीकी स्वाइन बुखार को रोकने के लिए मारे गए थे। मैं पशुधन के लिए भविष्य के खतरों से निपटने हेतु पशुधन और पोल्टरी के टीकाकरण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 25 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

51. हमने किसानों/पशुधन मालिकों को उनके दरवाजे पर पशु उपचार, मामूली सर्जरी, सैंपल क्लेक्शन और ऑडियो विजुअल समर्थन जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां एक रणनीतिक स्थान पर स्थित होंगी ताकि कम से कम समय में सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है।

52. कुल मिला कर पशुपालन क्षेत्र द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, मैं आगामी वित्तीय वर्ष में 605 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूँ, जो वित्त वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) से 9% अधिक है।

मछली पालन

53. हमारी सरकार नीली क्रांति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि करना चाहती है। अगले 5 वर्षों में झींगा की खेती के तहत वर्तमान क्षेत्र 1,212 एकड़

को 5,000 एकड़ तक विस्तारित करने की योजना है। मैं इस उद्देश्य के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

54. सरकार की सब्सिडी से जिला जालंधर में दो टन क्षमता की मिनी फिश फीड मिल स्थापित की गई है। किसान अब मामूली दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाली फ़ीड प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मछली, झींगा और इसके उत्पादों के संरक्षण के लिए 30 टन क्षमता का एक आइस-प्लांट सरकार की सब्सिडी से स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये प्रोजैक्ट और अन्य प्रोजैक्ट जो पाइपलाइन में हैं, निश्चित रूप से राज्य में मछली उत्पादन और किसानों की आय को बढ़ाएंगे।

वन और वन्यजीव

55. आप सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू की गई शहीद-ए-आजम स. भगत सिंह हरियावल लहर योजना के तहत 50 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 7,075 हेक्टेयर क्षेत्र में 54 लाख पौधे पहले ही लगाए जा चुके हैं। हमने विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।

56. मैने यह फ़ैसला किया है कि बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कागज के लिए जितने भी वृक्षों का उपयोग हुआ होगा, उस के एवज़ में अपने योगदान के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हमारे द्वारा बराबर की संख्या में पौधे लगाए जाएंगे।

57. 'ग्रीन पंजाब मिशन' के तहत 151 नानक बगीचियां और 68 पवित्र वन विकसित किए जा रहे हैं। हम अगले साल इतनी ही और नानक बगीचियां और पवित्र वन विकसित करेंगे।

58. वित्त वर्ष 2023-24 में वन एवं वन्यजीव विभाग के लिए 258 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन प्रस्तावित है, कुछ प्रमुख चल रहे कार्यक्रम/योजनाएं निम्नानुसार हैं:

क. पनकंपा- 196 करोड़ रुपए;

ख. वन्यजीव और चिड़ियाघरों का विकास - 13 करोड़ रुपए; और

ग. ग्रीन पंजाब मिशन - 31 करोड़ रुपए।

शिक्षा

माननीय अध्यक्ष महोदय,

59. शिक्षा आर्थिक विकास एवं सामाजिक प्रगति का इकलौता इंजन होता है, इस लिए शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना हर सरकार का कर्तव्य है। मैं स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए 17,072 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूँ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 % अधिक है।

स्कूल शिक्षा

60. हमारी सरकार गुणवत्ता और परिणाम आधारित शिक्षा को किसी भी समाज का स्तंभ मानती है। हम सिर्फ क्लास रूम बनाने और ब्लैक बोर्ड और फर्नीचर खरीदने पर ध्यान नहीं देंगे। शिक्षण के तरीके को बदलने पर ध्यान दिया जाता है और रहेगा। सभी प्रयासों का केंद्र प्रत्येक छात्र में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान योग्यता, अन्य जीवन कौशल और सब से ज़रूरी नैतिकता विकसित करना होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हमारी सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों को साझा करते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है:

- शिक्षण एवं गैर शिक्षण काडर के ठेका कर्मचारी जिन की संख्या हज़ारों में है, को

नियमित करने की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी।

- राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में दिसंबर, 2022 में मेगा-पैरेंट टीचर मीट (पीटीएम) का आयोजन किया गया। पीटीएम में 19 लाख अभिभावकों की उपस्थिति देखी गई और 3 लाख अभिभावकों से प्रतिक्रिया एकत्र की गई।

- आगामी बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के प्रदर्शन में सुधार लाने और 100% पास प्रतिशतता हासिल करने के उद्देश्य से "मिशन 100%: गिव योर बेस्ट" लॉन्च किया गया था।

- व्यावसायिक शिक्षा के तहत एक विशेष पहल की गई है जिसमें छात्रों को 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उनके ट्रेड के लिए विशिष्ट कौशल उपकरण किट प्रदान की गई ताकि पाठ्यक्रम पूरा होने के तुरंत बाद काम शुरू किया जा सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

- बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड (बाला) के सिद्धांत के अधीन स्कूलों को विकसित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7,700 स्कूलों को 4 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

सरकारी स्कूलों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता

61. हमारी सरकार ने पिछले बजट भाषण में किए गए वादे के अनुसार स्कूलों के रखरखाव और सभी सरकारी सीनीयर सैकेंडरी स्कूलों के लिए 'एस्टेट मैनेजर' के पद के निर्माण के लिए विधिवत नीति तैयार की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 99 करोड़ रुपए का आवंटन स्कूलों की बुनियादी सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित है, ताकि शिक्षक अपना ध्यान केवल शिक्षा पर केंद्रित कर सकें।

शिक्षकों/स्कूल प्रमुखों के लिए स्किल अप-ग्रेडेशन कार्यक्रम

62. किसी भी शिक्षा प्रणाली को प्रभावी और लाभकारी बनाने के लिए शिक्षकों का कौशल विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य अकादमी, सिंगापुर में 36 प्रधानाचार्यों/ शिक्षा अधिकारियों के पहले बैच को पांच दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया और 30 प्रधानाचार्यों का एक और बैच इस महीने में भेजा जा चुका है। अब हमारे विद्यार्थियों को पहले से अधिक प्रभावशाली तरीकों से पढ़ाया जाएगा। 'आप' सरकार हमारे सरकारी शिक्षकों को नवीनतम प्रशिक्षण देना जारी रखेगी। मैं इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखता हूँ।

स्कूलज़ आफ़ एमिनेंस

63. मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि किए गए वादे के अनुसार 117 स्कूलों को "स्कूलज़ ऑफ एमिनेंस" के रूप में अपग्रेड करने के लिए चिन्हित किया गया है। इन स्कूलों में से जिला अमृतसर के 04 स्कूलों में पायलट आधार पर अपग्रेडेशन का काम शुरू हो चुका है। इन्हें हब एंड स्पोक मॉडल पर संचालित किया जा रहा है, क्लस्टर के अन्य स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस से जोड़ा जाएगा। मैं देख सकता हूं कि ये स्कूलज़ ऑफ एमिनेंस शिक्षा के "विकास बिंदु" बन के उभरेंगे। उनके पास प्रशिक्षित फैकल्टी, खेल और अन्य पाठ्येतर गतिविधियाँ, करियर परामर्श और छात्रों के समग्र विकास के लिए सभी गतिविधियाँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्कूलों को प्रतिष्ठित स्कूलों में अपग्रेड करने के लिए 200 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट का प्रस्ताव रखता हूँ।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

64. मुझे इस पावन सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, हमारी सरकार द्वारा पिछले वर्षों से रुकी हुई 140 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि, ओबीसी छात्रों और अनुसूचित जाति के छात्रों को जारी की गई। मैं वित्तीय

वर्ष 2023-24 में ओबीसी छात्रों और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए क्रमशः 18 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव रखता हूं।

65. अब मैं शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रस्तावित आवंटन का संक्षिप्त उल्लेख करूंगा:

क. पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम द्वारा छात्रों के बीच वित्तीय और नेतृत्व कौशल विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत, सरकार 11वीं के छात्रों को उनके व्यावसायिक विचारों को प्रस्तावित करने हेतु प्रति छात्र 2,000 रुपये की दर से सीड मनी देकर सहायता प्रदान करती है और इस के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं;

ख. सरकारी स्कूलों में रूफ-टॉप सोलर पैनल सिस्टम की स्थापना- 100 करोड़ रुपए;

ग. सरकारी स्कूलों में चारदीवारी सहित बुनियादी ढांचे का उन्नयन- 324 करोड़ रुपए;

घ. 16.35 लाख छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराने के लिए - 456 करोड़ रुपए;

ङ. समग्र शिक्षा अभियान के तहत - 1,425 करोड़ रुपए;

च. प्री-प्राइमरी कक्षा के छात्रों को वर्दी प्रदान करने हेतु- 25 करोड़ रुपए; और

छ. नि:शुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने, मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए - 90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूं।

उच्च शिक्षा

66. यह सत्य है कि जब तक उच्च शिक्षा आधुनिक एवं प्रासंगिक नहीं होगी, हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र रोजगार योग्य नहीं होंगे। इस को ध्यान में हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य की ओर से निम्नलिखित पहलकदमियां करने का प्रस्ताव है:

रोजगार के लिए कोचिंग

67. मैं एतद्वारा 2 नई योजनाओं अर्थात रोज़गार और सॉफ्ट स्किल और कमियूनिकेशन ट्रेनिंग के लिए व्यावसायिक कोचिंग का प्रस्ताव रखता हूँ, जिस के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में उचित आवंटन किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत सरकारी कालेजों में समर्पित रोजगारपरक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर के छात्रों को व्यावसायिक आधार पर कोचिंग प्रदान की जायेगी।

बुनियादी ढांचे के लिए प्रावधान

68. वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में 11 नए कॉलेजों के निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। राज्य के सरकारी कालेजों में बुनियादी ढांचे के विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार तथा पुस्तकालयों के निर्माण के लिए 68 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

69. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के चरण 2 के तहत, राज्य सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में 70 करोड़ रुपए की लागत से गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए 6 केंद्र स्थापित करेगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर और पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला

द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के साथ साझेदारी में उद्यमिता हब स्थापित किए जा रहे हैं जो सामाजिक और औद्योगिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान परियोजनाओं और पेटेंट के प्रकाशन में मदद करेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस उद्देश्य के लिए 116 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है।

70. हमारी सरकार राज्य की पारंपरिक भाषाओं के प्रयोग को समर्थन और प्रोत्साहन देना जारी रखेगी। उर्दू अकादमी, मलेरकोटला के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं।

तकनीकी शिक्षा

अध्यक्ष महोदय,

71. मैं, राज्य के तकनीकी शिक्षा संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 615 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ जो वित्त वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) से करीब 6% ज्यादा है। मुझे विश्वास है कि यह संस्थान सक्षम और रोजगार योग्य इंजीनियरों और तकनीशियनों को सृजित करेंगे। इससे हमारे राज्य को समृद्ध होने में मदद मिलेगी क्योंकि प्रगति और विकास के लिए पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है।

72. मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि 13 साल के अंतराल के बाद 2009 से बंद कन्या राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, रोपड़ को वर्ष 2022 में फिर से खोल दिया गया है। सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 से इस कॉलेज को को-एजुकेशन कॉलेज के तौर पर चलाने की संभावना पर भी विचार कर रही है।

73. मुझे खुशी है कि प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से लालड़ू में प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीओटी) स्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23

में 137 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 28,607 प्रशिक्षुओं को दाखिला दिया गया है। सरकार ने इन प्रशिक्षुओं को ऑनलाईन-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, गोदरेज एंड बॉयस मैनुफ़ैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, हीरो साइकिल्स लिमिटेड और कई अन्य विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों के साथ 236 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

74. वित्त वर्ष 2023-24 में मौजूदा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई'ज़) के लिए बुनियादी ढांचे की अप-ग्रेडेशन, मशीनरी उपकरण और नए भवनों के निर्माण के के लिए; नए आईटीआई और पॉलिटेक्निक कालेजों को पूरा करने के लिए 63 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है।

75. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव): व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार और शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रसार के लिए, मैं वित्त वर्ष 2023-24 में इस उद्देश्य के लिए 40 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं।

खेल और युवा सेवाएं

76. अनुशासित और फिट आगुओं की एक पीढ़ी बनाने के लिए अपने युवाओं को खेलों की ओर वापस लाना हमारा कर्तव्य बनता है। पंजाबी युवाओं को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए राज्य में 14,500 से अधिक युवा क्लबों को फिर से सक्रिय करने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इस के साथ ही, पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार एक नई खेल नीति तैयार कर रही है जो खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद करेगी। खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न पहलकदमियों के लिए, मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 258 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश करता हूं, जो वित्त वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) से 55 प्रतिशत अधिक है।

77. हमारी सरकार ने युवाओं और प्रतिभावान खिलाडिय़ों का मनोबल बढ़ाने के दृष्टिकोण में बदलाव किया है। प्रारंभ में, ब्लॉक से राज्य स्तर तक एक खेल प्रतियोगिता "खेडां वतन पंजाब दीयां-2022" आयोजित की गई। इन खेलों में लगभग 3 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया और 9,961 विजेता खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की गई है।

78. हमारी सरकार ने प्रतिष्ठित "शहीद-ए-आज़म स. भगत सिंह राज युवा पुरस्कार" को फिर से शुरू किया है और इस के तहत प्रत्येक जिले से दो युवाओं को चुना जाएगा और एक पदक, 51,000 रुपए की राशि और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश भेजेगा और युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करेगा।

79. जिला स्तर और उप-मंडल स्तर पर बहुउद्देशीय खेल मैदान स्थापित किए जा रहे हैं और 46 करोड़ रुपए की 32 प्रोजैक्टों में से 33 करोड़ रुपए की लागत की 22 प्रोजैक्ट पूरे हो चुके हैं और शेष जल्द ही पूरे किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में खेल अधोसंरचना के निर्माण, उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 35 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। इसके अलावा, पी.पी.पी मोड के तहत विकसित की जाने वाली 10 खेल अवसंरचना प्रोजैक्टों की पहचान की गई है।

80. वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न कोचिंग सेंटरों, अकादमियों और खेल प्रकोष्ठों में कोचिंग करने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल सामग्री की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खेल उपकरणों की खरीद के लिए 3 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

81. पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से विशेष क्षेत्रों में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद है, मैं वित्त वर्ष 2023-24 में कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित दूसरे चरण के कार्यों

और इसके संघटक कॉलेजों के खर्च के लिए यूनिवर्सिटी के लिए 53 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखता हूं।

मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

82. पूरे विश्व में कहीं भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल अच्छी मेडिकल शिक्षा पर निर्भर करती है, जो रोगियों की सेवा और उपचार के लिए सक्षम डॉक्टर, नर्स और चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध कराती है। मैं मेडिकल शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,015 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूँ।

83. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोला गया है और पहले दो बैच में 100 एम.बी.बी.एस छात्रों को दाखिला दिया गया है एवं तीसरे बैच का दाखिला वित्तीय वर्ष 2023-24 में हो जाएगा।

84. मेडिकल संस्थानों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 880 स्टाफ नर्स और 81 पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है। साथ ही सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए नई नीति के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 300 विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति की गई है।

85. कपूरथला और होशियारपुर प्रत्येक में 100 एमबीबीएस सीटों वाले दो नए मेडिकल कॉलेजों को क्रमशः 422 करोड़ रुपए और 412 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है, जिन के डिज़ाइन मंजूर हो चुके हैं और जो शीघ्र ही आरंभ हो जाएंगे।

86. सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर में 119 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर रोगियों के लिए राज्य कैंसर संस्थान और फाजिल्का में 46 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर देखभाल

केंद्र जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

87. मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपए की कुल लागत से सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर और राजेंद्रा अस्पताल, पटियाला में ट्रॉमा सेंटर और जिला बरनाला में गांव ठीकरीवाल में एक नया नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायिलरी साइंसेज

88. राज्य में लिवर से सबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं और अधिकांश रोगियों को विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता होती है। पंजाब क्षेत्र में केवल पीजीआई अस्पताल, चंडीगढ़ ही है, जो ऐसे मामलों में उपचार प्रदान करने में माहिर है। जैसा कि हमारी सरकार ने वादा किया था, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में "पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायिलरी साइंसेज" स्थापित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरी तरह कार्यशील हो जाएगा। यह देश का दूसरा ऐसा संस्थान होगा जो व्यापक निदान और उपचार की सुविधा, उन्नत नैदानिक अनुसंधान और जिगर रोगों की रोकथाम प्रदान करेगा और इस संस्थान में रोगों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी तैनात किया जाएगा। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस संस्था के लिए 25 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान

89. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 990 करोड़ रुपये विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध कॉलेजों को जैसे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला, पी.ए.यू, गडवासु, श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ आदि और उन के संघटक कालेजों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव रखता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

90. आप सरकार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्यरत है। पिछले वर्ष में बताई गई दिशा अनुसार हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाएं, निदान समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। हमारा मानना है कि स्वस्थ आबादी वाला पंजाब ही निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 4,781 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं जो पिछले वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) से 11% अधिक है।

91. मैं इस पावन सदन को बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न श्रेणियों के तहत 1,353 कर्मचारियों / मेडिकल स्टाफ़ की भर्ती की गई है, जिनमें से 271 विशेषज्ञ मेडिकल अधिकारी, 3 फार्मेसी अधिकारी, 53 स्टाफ नर्स, 520 बहुउद्देश्यीय हेल्थ वर्कर, 480 वार्ड अटेंडैन्ट आदि शामिल हैं।

आम आदमी क्लीनिक (एएसीएस)

92. मुझे इस सम्मानित सदन को सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि 117 आम आदमी क्लीनिक स्थापित करने के प्रारंभिक लक्ष्य के मुकाबले, हमारी सरकार ने पहले ही 504 आम आदमी क्लीनिक स्थापित कर लिए हैं। अन्य 142 आम आदमी क्लीनिक तैयारी अधीन हैं और जिनके अगले कुछ दिनों में आरंभ होने की उम्मीद है। इन आम आदमी क्लीनिकों में 80 दवाएं और 41 डायग्नोस्टिक जांच निःशुल्क की जा रही हैं और अब तक 10.50 लाख से अधिक रोगियों ने मुफ़्त ओपीडी सुविधा का लाभ उठाया है और इन आम आदमी क्लीनिकों में 1 लाख से अधिक लैब परीक्षण किए जा चुके हैं।

सैकेंडरी स्वास्थय देखभाल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

93. हमारी सरकार ने राज्य में सभी माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों – कमिन्यूटी

हेल्थ सेंटरों, सब-डविजनल अस्पतालों और जिला अस्पतालों को मजबूत बनाने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इन अस्पतालों में न केवल एक बड़ा परिवर्तन लाया जाएगा, बल्कि मेडिकल अधिकारी (विशेषज्ञ) के 363 रिक्त पदों और मेडिकल अधिकारी (सामान्य) के 470 पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान भी चलाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मैं इन्हें और अन्य स्वास्थय केंद्रों की मज़बूती के लिए 39 करोड़ रुपए के प्रारंभिक खर्च का प्रस्ताव रखता हूं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच)

94. हमारे माननीय मुख्यमंत्री, सरदार भगवंत सिंह मान जी द्वारा फ़गवाड़ा एवं जगराओं में नए मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ अस्पतालों का उद्घाटन पहले ही किया जा चुका है और 3 मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ विंग्स अर्थात् सब-डविजनल अस्पताल नकोदर, सब-डविजनल अस्पताल खरड़ और सब-डविजनल अस्पताल बुढलाडा का निर्माण अब पूरा हो गया है और जल्द ही ये केन्द्र कार्यशील हो जाएंगे। सरकार ने 43 करोड़ रुपए की लागत से 7 नए मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ अस्पतालों की स्थापना और 37 करोड़ रुपए की लागत से 5 पुराने मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ विंग के अप-ग्रेडेशन के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। इस उद्देश्य के लिए, मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 16 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

आयुष

95. दयालपुर सोढ़ियां, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर और दुन्नेके (मोगा) में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल बनाए जा रहे हैं। दुन्नेके (मोगा) में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और दयालपुर सोढ़ियां, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और जल्द ही इनकी सेवाएं प्रदान होने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके लिए 18 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।

कैंसर स्क्रीनिंग मिशन

96. कैंसर ने हमारे राज्य में अनगिनत जीवन और परिवारों को नष्ट कर दिया है। मुझे याद है कि एक रेलगाड़ी जो पंजाबियों को बीकानेर के कैंसर अस्पताल ले कर जाती थी, उसे कैंसर एक्सप्रेस जैसा कुख्यात नाम दे दिया गया था। हमारी सरकार पंजाब में मौजूदा कैंसर उपचार बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्यव्यापी मिशन के रूप में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य इस खतरनाक बीमारी का शुरुआती चरण में ही पता लगाकर इसका सफल इलाज करना है।

97. उपरोक्त के अलावा, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में की जाने वाली कुछ प्रस्तावित पहलकदमियों की एक झलक देना चाहूँगा।

- औषधि प्रबंधन सुविधाओं और केंद्रों का संचालन और उन्नयन - 40 करोड़ रुपए;
- होमी भाभा कैंसर सेंटर के लिए पैट और स्पैक्ट सीटी स्कैन मशीनों की खरीद- 17 करोड़ रुपए; और
- 24 घंटे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा - 61 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं।

रोजगार सृजन और कौशल विकास

अध्यक्ष महोदय,

98. अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के पहले साल में पंजाब राज्य के 26,797 नौजवानों को रोजगार दिया जा चुका है और 22,594 पदों को भरने के लिए विज्ञापन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हमारे भाई-बहनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी हमारी सरकार ने वादे के अनुसार पूरा किया जा रहा है, ठेके पर रखे, एडहॉक और वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित करने की नीति

को मंजूरी दे दी गई है और प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। मैं वित्त वर्ष 2023-24 में रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए 231 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करता हूं जो पिछले वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) से 36% अधिक है।

कौशल विकास

99. हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि युवाओं के लिए प्रशिक्षण, नए कौशल और तकनीकों को सीखने, करियर में उन्नति और अवसरों को बढ़ावा देने का मौका प्रदान करता है। उद्योग और कौशल की खाई को पाटने के लिए, सरकार ने अलग-अलग एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन किया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 5,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा।

100. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि जैसी प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 163 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं।

उद्योग और वाणिज्य

अध्यक्ष महोदय,

101. मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ कि पिछले 11 महीनों के दौरान, पंजाब को लगभग 41,043 करोड़ रुपए की राशि के 2,295 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आशा की जाती है कि नए निवेश से आने वाले समय में लगभग 2.5 लाख से लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

102. इसके साथ ही, प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट में 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय और विदेशी व्यापारिक आगुओं ने जोर-शोर से भाग लिया, जिन्होंने पंजाब और इसके उज्जवल भविष्य में अपनी पूरी रुचि दिखाई। हमारी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कानूनी

ढांचा और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हमारी सरकार के संकल्प को दर्शाने के लिए 5 नीतियां बनाई हैं- औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति, पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति, लाजिस्टिक और लाजिस्टिक पार्क नीति, जल पर्यटन नीति और साहसिक पर्यटन नीति को लागू किया गया है।

103. अगले 5 वर्षों में मजबूत निवेश आकर्षित करने और अधिकतम रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से व्यापक हितधारक परामर्श के बाद नई औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति, 2022 को 08.02.2023 को विधिवत रूप से अधिसूचित किया गया है। हमारी सरकार एम.एस.एम.ई के विकास में तेजी लाने के लिए 20 ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टर, 15 औद्योगिक पार्क विकसित करने की परिकल्पना करती है और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सर्वोत्तम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करके स्टार्ट-अप और इनोवेशन पर भी जोर देगी।

104. उच्च वित्तीय प्रोत्साहन के उद्देश्य से "थ्रस्ट सेक्टर" के वर्ग में इलेक्ट्रिक वाहन सहित ऑटो/ऑटो कलपुर्ज़ों का निर्माण, फिटनेस उपकरण सहित खेल के सामान, बिजली उपकरण और मशीन उपकरण सहित हैंड टूल्ज़, कृषि मशीनरी और उपकरण, पेपर आधारित पैकेजिंग युनिट, श्रेडिंग आधारित प्रबंधन युनिट एवं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नीति में ईंधन के रूप में धान की पराली के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया है।

वित्तीय प्रोत्साहन

105. हमारी सरकार उद्योगों को सहयोग जारी रखेगी, जिसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 3,751 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान का प्रस्ताव है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) से 19% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2023-24 में औद्योगिक इकाइयों को पूंजीगत सब्सिडी के लिए 75 करोड़ रुपए एवं औद्योगिक फोकल पॉइंट के लिए 50 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं।

106. विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को 100% बिजली शुल्क छूट, 26 औद्योगिक इकाइयों को एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए 7 औद्योगिक इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र (ईसी) के रूप में 895 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

107. राज्य में स्थित औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 2,700 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है और वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 3,133 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं।

शासन सुधार

108. एक अच्छा शासन देना हमारी सरकार का उद्देश्य है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से कुशल, पारदर्शी और सुलभ प्रशासन के लिए एक वातावरण बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। हमारी सरकार ने राज्य भर में संचालित 535 सेवा केंद्रों में 110 नई सेवाएं शुरू की हैं। फ्लैगशिप कार्यक्रम "सरकार आपके द्वार" जिस के तहत नागरिक केंद्रित सेवाओं को घर-घर पहुंचाने के लिए “आप” सरकार लगातार काम कर रही है।

109. राज्य डेटा नीति को ऐसे प्लेटफार्मों के काबिल बनाने के लिए कारयशील बनाया जा रहा है जिससे विभागों के पास उपलब्ध डाटा की अंतर-कार्यशीलता बढ़ाकर नागरिकों को बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी।

110. विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 77 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं, जिसमें आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपए शामिल हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

111. खरीफ़ मंडीकरन सीजन 2022-23 में हमारी सरकार ने धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए। सरकारी खरीद एजेंसियों ने 182.11 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की और लगभग 8 लाख किसानों के खातों में 37,514 करोड़ रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य पारदर्शी रूप से जमा किया गया।

112. हमारी सरकार ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 1.48 करोड़ लाभार्थियों को 4.61 लाख मीट्रिक टन गेहूं का वितरण किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र और गरीब परिवारों को ही मिले, अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

113. हमारी सरकार डिफाल्टर राइस मिलर्स के लंबित मामलों को निपटाने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखती है। इस योजना के माध्यम से मिल मालिकों को कम ब्याज और कम वसूली योग्य राशि का भुगतान कर बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू करने का अवसर मिलेगा। आवंटन प्रक्रिया के दौरान अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार अगले खरीफ मंडीकरण सीज़न से मंडियों को चावल मिलों से ऑनलाइन जोड़ने की भी योजना बना रही है।

राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन

114. हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के नेतृत्व में कार्य प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए कई उपाय किए हैं। ई-गवर्नेंस पहलकदमी जैसे कि ई-स्टांपिंग; पेपर लिए जा सकते हैं; पुराने/प्राइवेट पार्टीशन को कारगर बनाने के लिए एक वेबसाइट; खसरा गिरदावरी (ई-गिरदावरी) की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग; राज्य के राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली; अवं अन्य कदम।

115. प्राकृतिक आपदाओं के समय आने वाली कठिनाई के समय किसानों को नियमित मदद दी गई, इस संबंध में फसल/पशुधन/घर आदि के नुकसान के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 125 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया जा चुका है।

116. हमारी सरकार हमारे नागरिकों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शिता को यकीनी बनाने के लिए राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं को मजबूत बनाना जारी रखेगी वित्तीय वर्ष 2023 24 में इस विभाग के लिए 1,834 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं।

एन.आर.आई. मामले

117. एनआरआई को सक्रिय रूप से जोड़ने और उनसे आमने-सामने मिलने के लिए हमारी सरकार की अनूठी पहल "एनआरआई पंजाबियां नाल मिलनी" कार्यक्रम एक बड़ी सफलता रही है। प्रवासी भारतीयों ने पहली बार महसूस किया है कि पंजाब में एक पारदर्शी सरकार है, जो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए गंभीर है। मैं इस पावन सदन को बताना चाहता हूं कि इन मिलनियों से कई एनआरआई की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। उदाहरण के लिए मोगे जिले के रोडे गांव की सफलता की कहानी, जिसमें यू.के स्थित एनआरआई द्वारा 17.5 एकड़ भूमि वापिस दिलवाई गई, सुर्खियों में भी रही।

118. हमारी सरकार ने "पंजाब सिखिया ते सेहत फंड" स्थापित करने का वादा किया था। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब पंजाब सिखिया ते सेहत फंड ट्रस्ट पंजीकृत हो गया है। भारत सरकार से कानून के अनुसार आगे की आवश्यक मंजूरियां ली जा रही हैं और मुझे विश्वास है कि वित्त वर्ष 2023-24 में ट्रस्ट सक्रिय हो जाएगा और मेरे एनआरआई भाई-बहन अपनी मातृभूमि के विकास में सीधे योगदान दे सकेंगे।

रक्षा सेवाएं कल्याण

119. इस देश की रक्षा और सुरक्षा में पंजाब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सैनिकों के परिवारों की देखभाल करें, जिन्होंने इस महान देश के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 84 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

120. हमारी भावी पीढ़ियों को हमारे सम्मानित सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों से सीखना और प्रेरित होना चाहिए, इसलिए मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अमृतसर में युद्ध स्मारक परिसर की दो नई गैलरियों की अप-ग्रेडेशन और स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूँ।

121. इस के साथ ही, सैनिक स्कूल, कपूरथला के रखरखाव के लिए 3 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूँ।

पर्यटन और सांस्कृतिक मामले

122. पंजाब को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने और इसे पसंदीदा पर्यटन स्थान बनाने के प्रयास पहले ही शुरू हो चुके हैं। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में ढांचागत विकास को गति दी है। मैं इस क्षेत्र के लिए 281 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूँ जो वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) से 8% अधिक है।

123. प्रदेश की पर्यटन संबंधी अनेक संपत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए 9 प्राइवेट पार्टियों से अनुबंध किया गया है। खटकड़ कलां में शहीद भगत सिंह संग्रहालय का अप-ग्रेडेशन कार्य चल रहा है; ऐतिहासिक-सैन्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एंग्लो-सिख वार सर्किट विकसित किया जाएगा और सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला में विरासत परिसर 'पिंड बाबे नानक दा' विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा, पर्यटन की

संभावना वाले कई अन्य स्थलों की पहचान की गई है जिन्हें पीपीपी मोड के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

124. राज्य में विभिन्न स्मारकों के निर्माण, रखरखाव और जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 110 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। इसके अलावा, 32 करोड़ रुपए की लागत से श्री चमकौर साहिब को प्रशाद स्कीम के तहत विकसित किया जा रहा है और हमने इस योजना के तहत अमृतसर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ "दुर्गियाना मंदिर" और श्री आनंदपुर साहिब को शामिल करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है।

125. पंजाब को एक टूरिस्ट ब्रांड बनाने और इस के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रोड शो, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से इस का प्रचार करने के लिए मैं 5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूं।

पुलिस और कानून व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय,

126. कुछ बुरी ताकतें हमेशा हमारे सीमावर्ती राज्य में शांति और व्यवस्था को बिगाड़ने के अवसरों की तलाश में रहती हैं। अतीत में किए गए ऐसे प्रयासों का मुकाबला हमारे बहादुर पुलिस बलों ने बड़े साहस से सफ़लतापूर्वक किया था। मैं अपनी सरकार की ओर से पंजाब के दुश्मनों को चेतावनी देता हूँ कि वे कानून का पालन करें नहीं तो हमारी सरकार उन्हें जड़ से खत्म कर देगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैं 10,523 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं जो वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) से 11% अधिक है।

127. हमारी सरकार हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पुलिस बलों को सभी बाधाओं के लिए तैयार कर रही है। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग को नवीनतम उपकरणों और बुनियादी ढांचे के साथ मजबूत बनाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 40 करोड़

रुपए का खर्च प्रस्तावित है।

128. गैंगस्टर कल्चर का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और कानून व्यवस्था तंत्र में लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिए, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने राज्य में गैंगस्टरों और अपराधियों के खिलाफ समर्पित अभियान चलाए हैं। फ़रवरी, 2023 के अंत तक एजीटीएफ ने 567 गैंगस्टर/अपराधियों को गिरफ्तार करने, 05 गैंगस्टरों को मार गिराने, 156 गैंगस्टर/आपराधिक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए 563 हथियार और 125 वाहन बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। अपराध से निपटने और कानून व्यवस्था कायम रखने और राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस बलों को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 64 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

129. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सीमावर्ती जिलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 40 करोड़ रुपए के प्रारंभिक बजट का प्रस्ताव रखता हूं, जिस का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने; रोशनी की अच्छी व्यवस्था करने; आने-जाने के लिए अत्याधुनिक वाहनों आदि की खरीद हेतु किया जाएगा।

130. आज दुनिया साइबर युद्ध और साइबर अपराध जैसे नवीनतम और प्रबुद्ध खतरे का सामना कर रही है। हमारी सरकार साइबर अपराध व्यवस्था का आधुनिकीकरण करेगी और इसकी क्षमताओं को बढ़ाएगी; मैं वित्त वर्ष 2023-24 में साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने में उनकी मदद करने के लिए 30 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

131. मैं वित्त वर्ष 2023-24 में पुलिस लाइन, पुलिस स्टेशनों और अन्य पुलिस कार्यालयों के लिए भूमि की खरीद के लिए 33 करोड़ रुपए और पुलिस परिसरों और भवनों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

132. इसके अलावा, हुडको से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए पुलिस आवास निगम की सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 26 करोड़ रुपए की विशेष सहायता का

प्रावधान किया गया है।

सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय

133. सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और नीतियों को जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वे सम्मान का जीवन जी सकें। हमारी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करती रहेगी, जिसके लिए मैं वित्त वर्ष 2023-24 में 8,678 करोड़ रुपए के बजटीय खर्च का प्रस्ताव रखता हूँ जो कि वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) की तुलना में 17% की वृद्धि है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

134. राज्य के 31.59 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं, अनाथ बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मैं यह बताना चाहूँगा कि जुलाई 2022 में एक सर्वे किया गया था, जिसके मुताबिक 90,248 लाभार्थी मृत पाए गए थे। 83,372 लाभार्थियों के वारिसों से 24 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है और शेष की वसूली प्रक्रियाधीन है। मैं 33.26 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 5,650 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ, जो वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) की तुलना में 1,002 करोड़ रुपए और 22% अधिक है।

135. वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे पोषण अभियान; प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना; सुग्मय भारत अभियान, आदि के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। इस के अलावा, महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 497 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।

136. इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, आशीर्वाद योजना और प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।

137. हमारी सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और समाज के सभी कमज़ोर वर्गों के सशक्तिकरण, संरक्षण और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 13,878 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

बुनियादी ढांचा

अध्यक्ष महोदय,

138. जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, इस वर्ष प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक विवेकपूर्ण पूंजीगत व्यय के माध्यम से ढांचागत विकास को प्राथमिकता देना होगा। यह सच है कि कार्यात्मक बुनियादी ढांचे के मजबूत नेटवर्क के बिना कोई भी देश या क्षेत्र लंबे समय तक सफल नहीं रहा है। हमारी सरकार ने आगामी वर्ष में पूंजीगत खर्च की एक रणनीति तैयार की है। मैं राज्य के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और उन्नयन से संबन्धित कार्यालयों के लिए कुल 26,295 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश करता हूं। यह प्रावधान पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) से 13% अधिक है।

सड़कें और पुल

139. हम वित्त वर्ष 2023-24 में सड़कों, पुलों और भवनों का निर्माण और रखरखाव कार्य करेंगे, जिसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) में 1,495 करोड़ रुपए के मुकाबले बजटीय आवंटन बढ़ाकर 3,297 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में की जाने वाली कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं:-

- सड़कों और पुलों के नवीनीकरण, निर्माण और मरम्मत के लिए 1,101 करोड़;

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत 1,278 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के उन्नयन के लिए 600 करोड़; और
- मैं केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत 454 किलोमीटर सड़कों के कार्यों के लिये 190 करोड़ रुपये की के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं।

140. मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,992 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 12,897 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कों की मरम्मत के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाने का भी प्रस्ताव रखता हूं। इन सड़कों की मरम्मत का कार्य पिछले 06 वर्षों से लंबित है।

ग्रामीण विकास और पंचायतें

141. हमारी सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत 9447 एकड़ शामलात भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करावाया गया है। इस मुक्त भूमि का उपयोग अब संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा गांवों में विकास कार्यों और राजस्व सृजन के लिए किया जा सकता है।

142. पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र और व्यापक विकास के अपने वादे पर आगे बढ़ते हुए, मैं वित्त वर्ष 2023-24 में 3,319 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूं जो वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) से 11% अधिक है। समार्ट विलेज कैंपेन के तहत कुल 77,986 कार्यों में से 68,825 कार्य 4,092 करोड़ रुपए के निवेश से पूरे किए गए हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 में 8.12 लाख परिवारों को 285 लाख दिहाड़ी दिवसों द्वारा रोजगार प्रदान किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए निम्नलिखित आवंटन प्रस्तावित किए जा रहे हैं:

क. मनरेगा: रोजगार प्रदान करने के लिए 655 करोड़ रुपए।

ख. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 घरों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए।

ग. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन: 50 करोड़ रुपए।

घ. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: 20 करोड़ रुपए।

ङ. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान: 80 करोड़ रुपए।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

143. हमारी सरकार ने भूजल से सतह आधारित जल आपूर्ति की नीति अपनाई है। भारी धातुओं और आर्सेनिक की मौजूदगी वाले खराब पानी की गुणवत्ता वाले क्षेत्र और पानी की कमी वाले क्षेत्र प्राथमिकता सूची में हैं। 11859 गांवों, 146 ब्लॉकों और 20 जिलों में 100% सैचुरेशन सुनिश्चित की गई है और 170 सीमावर्ती गांवों के 20,471 परिवारों को आर्सेनिक हटाने के लिए घरेलू शोधक प्रदान किए गए हैं।

144. मैं जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यों और परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,987 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं, जो वित्त वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 27% अधिक है। निम्नलिखित योजनाओं के लिए बजट प्रस्ताव इस प्रकार हैं-

क. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): 400 करोड़ रुपये।

ख. जल जीवन मिशन: 200 करोड़ रुपये।

ग. जल-आपूर्ति संबंधी अधोसंरचना की मरम्मत एवं संभाल हेतु 20 करोड़ रुपए।

घ. साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में 40 करोड़ रुपए के निवेश से जल भवन का निर्माण।

जल संसाधन

145. हमारी सरकार हमारी नहर प्रणाली के अंत तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। नहरों की सफाई व सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मैं वित्त वर्ष 2023-24 में चल रहे कार्यों और अन्य नई परियोजनाओं के लिए 2,630 करोड़ रुपए जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) से 15% अधिक है, के खर्च का प्रस्ताव करता हूं, जिसका विवरण निम्नलिखित पैरों में दिया गया है:

146. मुझे इस पावन सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि फिरोजपुर, ममदोट, गुरु हरि सहाय, जलालाबाद और फाजिल्का के सीमावर्ती क्षेत्रों में चमड़ा उद्योग से निकलने वाला गंदा पानी पूर्वी नहरों - सतलुज नदी में गिरता था, जिससे पानी पीने या सिंचाई के लिए अनुपयुक्त हो गया था; जनवरी 2023 से किसानों की इस मांग का उचित समाधान किया गया है और फीडर के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति शुरू हो गई है और इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो नहरें केवल खरीफ सीजन में चलती थीं, वे अब साल भर चलेंगी।

नहरी प्रबंधन

147. **सरहिन्द फीडर एवं राजस्थान फीडर की रिलाइनिंग :** वर्ष 2019-20 से अब तक, सरहिंद फीडर के लगभग 84 किलोमीटर और राजस्थान फीडर के 62 किलोमीटर की रिलाइनिंग और पक्की संरचना का काम क्रमशः 500 करोड़ रुपए और 735 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान शेष 16 किमी और 34 किमी की शेष लंबाई के लिए रीलाइनिंग और पक्की संरचना का काम किया जाएगा।

148. **लिफ्ट सिंचाई योजना:** श्री आनंदपुर साहिब जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 03 लिफ्ट सिंचाई कार्यों में से एक पूरा हो चुका है और दूसरा निर्माणाधीन है और मार्च, 2023 तक इस के पूरा होने की उम्मीद है। मैं वित्त वर्ष 2023-24 में तीसरे लिफ्ट

सिंचाई कार्य के लिए 80 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

149. **डिस्टीब्यूट्री सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंग:** मैं वित्त वर्ष 2023-24 में अरनौली डिस्टीब्यूट्री, भवानीगढ़ डिस्टीब्यूट्री, खन्ना डिस्टीब्यूट्री; नवादा डिस्टीब्यूट्री सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंग के लिए 309 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। इनके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2023-24 में नारायणगढ़ माइनर का आधुनिकीकरण; कंगनवाल डिस्टीब्यूट्री सिस्टम आदि के पुनर्वास का प्रस्ताव रखता हूं।

स्थानीय सरकार और शहरी विकास

150. बढ़ते शहरीकरण पर ध्यान देने और विश्व स्तरीय योजनाबद्ध टाउनशिप विकसित करने के लिए, शहरी विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत नई टाउनशिप के लिए अपनी योजना तैयार करें।

151. इस संबंध में, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक भूखंडों के विकास के लिए साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में 1,600 एकड़ क्षेत्र में एक नया अर्बन एस्टेट विकसित कर रही है।

152. न्यू चंडीगढ़ में 1,000 एकड़ में कम घनता वाली ईको सिटी-3 नाम से अर्बन एस्टेट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

153. वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा लुधियाना में 1,600 एकड़ जमीन पर अर्बन एस्टेट स्थापित किया जाएगा और बठिंडा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बठिंडा में करीब 200 एकड़ की टाउनशिप भी विकसित की जाएगी।

154. यह जिक्र योग्य है कि सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन, पूर्णता प्रमाण पत्र, लेआउट और बिल्डिंग प्लान देने के लिए विकास प्राधिकरणों के स्तर तक शक्तियाँ विकेन्द्रीकृत की

हैं। प्रक्रिया सरलीकरण के ऐसे ही एक अन्य कदम में, भवन निर्माण योजनाओं के अनुमोदन और स्टैंड-अलोन उद्योगों को पूर्णता प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार डायरैक्टर, फ़ैक्टरीज़ को सौंपा गया है।

155. विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर भारत को तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है तो अगले 15 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे में 840 बिलियन डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी। इस हकीकत को समझते हुए हमारी सरकार शहरी विकास और स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दे रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए 6,596 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखता हूं।

156. इसमें से अमरुत योजना के तहत 1,149 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत 425 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस के साथ ही सतही जलापूर्ति लुधियाना व अमृतसर के लिए 460 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 412 करोड़ रुपये, पंजाब म्युनिसिपल डेवलपमेंट फंड के लिए 250 करोड़ रुपये और बी.आर.टी.एस अमृतसर के लिए वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं।

माइनिंग

157. सरकार ने पहली बार लुधियाना, फाजिल्का, तरनतारन, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, रूपनगर और शहीद भगत सिंह नगर नगर में 33 सार्वजनिक खनन स्थलों को आम जनता के लिए रेत के उपयोग के लिए चालू किया है एवं 117 और सार्वजनिक खनन स्थल शीघ्र ही शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, न्यू पंजाब स्टेट सैंड एंड ग्रेवल माइनिंग पालसी नीति, 2023 को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसके द्वारा सरकार ने रेत और बजरी को जनता के लिए सस्ता करने के लिए पिट हेड दरों को 9 रुपए / प्रति घन फ़ुट से घटाकर 5.5 रुपए / प्रति घन फ़ुट कर दिया है।

158. उपरोक्त के अलावा, राज्य में माइनर खनिजों और खनन गतिविधियों में शामिल सभी वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा और अब तक 4,400 से अधिक वाहनों का पंजीकरण किया जा चुका है; अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में 27 अंतर्राज्यीय जांच चौकियां स्थापित की गई हैं; अवैध खनन या अधिक दर वसूलने से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।

ट्रांसपोर्ट

159. ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में बड़े सुधार शुरू किए गए हैं। हमारी सरकार ने पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति को हाल ही में अधिसूचित किया जा चुका है। इस का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का है। सरकार ने पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधा लागू की है। स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने के लिए संभावित स्थानों की पहचान कर ली गई है और वित्त वर्ष 2023-24 में इसे चालू कर दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार का प्रस्ताव पी.आर.टी.सी और पंजाब रोडवेज के सभी डिपो में इंटीग्रेटेड डिपो मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने का है।

160. अल्ट्रा-मॉडर्न उपकरणों के साथ वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस की जांच करने के लिए, सरकार राज्य में साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, बठिंडा, लुधियाना, फरीदकोट और अमृतसर में बिल्ड, ओन एंड आपरेट आधार पर 6 ऑटोमोटिव परीक्षण स्टेशनों का निर्माण, स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है।

161. मैं ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के लिए 567 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं जो वित्तीय वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) की तुलना में 42% की वृद्धि है, जिसमें से राज्य में 28 बस स्टैंडों की चरणबद्ध स्थापना/अपग्रेडेशन के लिए 35 करोड़ रुपए और पंजाब राज्य सड़क सुरक्षा फ़ंड के लिए 48 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं।

बिजली

162. इस साल राष्ट्रव्यापी कोयला संकट के बावजूद, पंजाब ने अप्रैल-सितंबर, 2022 के दौरान 14,311 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक मांग को पूरा किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि है। बिजली संयंत्रों में कोयले की गंभीर कमी के बावजूद हमारी सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को नियमित 8 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की।

163. मैं इस सम्मानित सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पी.एस.पी.सी.एल को नियमित सब्सिडी भुगतान जारी रखा। इस से पहले पी.एस.पी.सी.एल की सब्सिडी की मांग कभी भी समय पर पूरी नहीं होती थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी प्रदान करने हेतु 7,780 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं।

164. माननीय मुख्यमंत्री, सरदार भगवंत सिंह मान जी के प्रयासों से, पंजाब की पछवाड़ा कोयला माइन, जो पिछले 7 वर्षों से बंद थी, अब शुरू हो गई है। इस खदान के चालू होने से, पी.एस.पी.सी.एल प्रति वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए की बचत करने में सक्षम होगा।

165. पीएसपीसीएल को सुधार-आधारित और रिज़ल्ट-लिंक्ड रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। हमारी सरकार अगले 5 वर्षों में पीएसपीसीएल को 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया सब्सिडी भुगतान को क्लीयर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बकाया सब्सिडी 2014-15 से एकत्र हो रही थी। आर.डी.एस.एस योजना के तहत, 9,642 करोड़ रुपए की राशि के वितरण बुनियादी ढांचे के काम और मीटरिंग के काम जैसे कि मिश्रित फीडरों का पृथक्करण, फीडरों का द्विभाजन, नया वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी), आदि 5 वर्षों की अवधि में किए जाएंगे। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बिजली सब्सिडी बकाया और उस पर ब्याज के क्रमशः 1,804 करोड़ रुपये और 664 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

166. वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 2,227 मेगावाट है जो कि राज्य की कुल स्थापित क्षमता का 16% लगभग है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के अनुरूप 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्थापित क्षमता के 50% तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

167. हमारी सरकार कम्प्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, जो प्रति वर्ष 16.54 मिलियन टन अधिशेष धान के पुआल का उपयोग कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सीबीजी परियोजनाओं में धान के पुआल के उपयोग को 5 से 6 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाना है।

168. आप सरकार का इरादा वर्ष 2030 तक राज्य के पूरे कृषि पंप सेटों को सोलराइज करने के मिशन के साथ अगले पांच वर्षों में सभी डीजल-आधारित कृषि पंप सेटों को सोलराइज करने का है।

नागरिक उड्डयन

169. दुनिया के साथ जुड़ाव किसी भी राज्य के लिए नए अवसर लाता है और नए रास्ते खोलता है। पंजाब सौभाग्यशाली है कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में पंजाबी प्रवासी हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और हमारे हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मोहाली के टर्मिनल भवन के दूसरे चरण के निर्माण पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। हमारी सरकार ने भारतीय वायु सेना स्टेशन, हलवारा, लुधियाना में टर्मिनल भवन के विकास के लिए 57 करोड़ रुपए का योगदान देने का फ़ैसला किया है और यह कार्य मई, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है और दिसंबर, 2023 तक उड़ान संचालन शुरू होने की आशा है।

170. सरकार ने शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मोहाली में एयर कार्गो सुविधाओं का विस्तार करने और श्री गुरु राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर पर पेरिशेबल कार्गो कॉम्प्लेक्स के संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के साथ दो अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

राजस्व वृद्धि और बकाया ऋण

अध्यक्ष महोदय,

171. चालू वर्ष में राज्य की अपनी कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि से हमारी सरकार की ईमानदार मंशा स्पष्ट होती है। पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में राज्य के स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व दोनों में वृद्धि हुई है। अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) में राज्य जीएसटी 23%, राज्य उत्पाद शुल्क 45%; स्टांप्स और पंजीकरण 19%; वाहनों पर कर 12% और गैर-कर राजस्व 26% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

172. वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 98,852 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से स्वयं का कर-राजस्व 51,835 करोड़ रुपए और गैर-कर राजस्व 7,824 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय करों का हिस्सा 18,458 करोड़ रुपए और केंद्र से सहायता अनुदान 20,735 करोड़ रुपए आंका गया है।

173. वित्तीय लेनदेन को औपचारिक रूप देने, उपभोक्ता को जागरुक करने और जीएसटी राजस्व को बढ़ाने के लिए, मैं वित्त वर्ष 2023-24 में "बिल लाओ इनाम पाओ" योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इस योजना के तहत जो लोग/उपभोक्ता अपने बिल कराधान विभाग के पास जमा करवाएंगे, और उन में से ड्रा निकाल कर पुरस्कार दिए जाएंगे।

174. हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पिछली सरकारों द्वारा लिए गए ऋण पर मूलधन के 15,946 करोड़ रुपए और ब्याज के 20,100 करोड़ रुपए वापिस किए। आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हमारी सरकार 16,626 रुपए के मूलधन एवं 22,000 रुपए के ब्याज की भारी-भरकम रकम का भुगतान करेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी प्रभावी बकाया ऋण 46.81% होने का अनुमान है।

निष्कर्ष

माननीय अध्यक्ष महोदय,

175. सही इरादे, नेक सोच और सार्वजनिक जीवन में साफ़-सुथरी छवी का साहस राजनीति और राष्ट्र को बदलने की ताकत रखता है। आम आदमी पार्टी सरकार को ये गुण और प्रेरणा उसके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलती है। मैं, अपनी पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से पांच दरियाओं की इस महान भूमि की खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए समर्पण और ईमानदारी के साथ सेवा करते रहने का वादा करता हूं।

176. मैं, हमारी आशा की किरण, सरदार भगवंत सिंह मान जी को एक अद्वितीय नेतृत्व प्रदान करने के लिए उन का धन्यवाद करना चाहता हूं। पंजाब के पुनरुद्धार के लिए उनका जुनून हमें प्रेरित करता है और सार्वजनिक हित के लिए सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है।

177. अंत में, मैं वित्त विभाग और योजना विभाग के अधिकारियों की कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों की सराहना करता हूं, जिन्होंने इस जटिल कार्य को पूरा करने के लिए पूरी संजीदगी के साथ दिन-रात काम किया।

178. इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द